'लेवी शुगर के कैरी फॉरवर्ड का नियम हटे'

[रितुराज तिवारी *नई दिल्ली*]

लेवी चीनी की बची हुई मात्रा के कैरी फॉरवर्ड का नियम हटवाने के लिए चीनी उद्योग लॉबीइंग में जुटा है। सरकार के लेवी चीनी से जुड़े नियम को पूरा करने के लिए चीनी मिलों को प्रत्येक वर्ष अपने उत्पादन का 10 फीसदी सब्सिडी वाली दरों पर बेचना पड़ता है। लेवी चीनी की कीमत 1,900 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में चीनी 2,900 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रही है।

इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (इस्मा) ने खाद्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इस नियम को हटाने की मांग की है। इस्मा के डायरेक्टर अविनाश वर्मा ने कहा, 'पिछले छह वर्षों में सरकार अपनी 26 लाख टन की जरूरत में से लेवी चीनी का 50 फीसदी भी उठाने में नाकाम रही है। इससे मिलों के लिए इनवेंटरी की समस्या पैदा होती है।'

लेवी चीनी की कीमत बहुत कम...

लेवी चीनी की कीमत 1,900 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में चीनी 2,900 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रही है

वर्मा ने कहा, 'लेवी चीनी की मात्रा का नियम प्रत्येक सीजन के अंत में खुद ही समाप्त हो जाना चाहिए। इससे मिलों को स्टॉक बेचने की विकल्प मिल सकेगा। इस वर्ष भी सरकार 21 लाख टन का लेवी स्टॉक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, जिससे सीजन के अंत तक लगभग 40 लाख टन की लेवी इनवेंटरी हो सकती है।' सरकार ने मौजूदा सीजन में 26 लाख टन के कुल लेवी स्टॉक में से केवल 1.81 लाख टन उठाया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें इस नियम को समाप्त करने के लिए इस्मा और अन्य चीनी मिलों से निवेदन मिले हैं। यह नीतिगत मसला नहीं है बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। लेवी चीनी पर किसी भी नियम के लिए सरकार से स्पष्ट निर्देश की जरुरत है।'

हालांकि, 2010 में सरकार ने आवंटन के तीन महीनों के अंदर कोटा का इस्तेमाल न होने पर मिलों को लेवी स्टॉक की बची हुई मात्रा खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी थी। लेकिन इससे मिलों को मदद नहीं मिल रही, क्योंकि उन्हें बाद में सरकार की मांग पर लेवी की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। वर्मा ने कहा, 'प्रत्येक वर्ष उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और इसके साथ ही चीनी की कीमत भी। लेकिन मांग को पिछले वर्ष के लेवी कीमत से पूरा करना होता है, जो मौजूदा लेवी कीमत से कम होती है। मिलों को इनवेंटरी की लागत उठानी पड़ती है।'